



टिकट बिकेगा नहीं, चुना जाएगा।

दिल्ली से शुरू होने वाली एक प्रस्तावित नई पार्टी, जो एक विचार पर आधारित है: **हर उम्मीदवार नेता नहीं, सदस्य चुनेंगे** — और भ्रष्टाचार राजनीति की कीमत नहीं, निष्कासन का कारण माना जाएगा।

पार्टी किसके लिए खड़ी है

इसका सर्वोपरि उद्देश्य भ्रष्टाचार-मुक्त भारत है। इसका लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और संविधान में विधिसम्मत संशोधन के माध्यम से आरक्षण को जाति के बजाय आर्थिक आवश्यकता पर आधारित करना भी है।

दस बातें जो इसे अलग बनाती हैं

1. हर उम्मीदवार सदस्य चुनेंगे

सीधी बहस के साथ खुली ऑनलाइन प्राइमरी। उम्मीदवार को 50% से अधिक मत चाहिए, वरना शीर्ष दो के बीच दूसरा चरण।

2. टिकट कभी नहीं बिकेगा

टिकट के लिए पैसा देने या लेने पर उम्मीदवारी रद्द और पार्टी से निष्कासन।

3. संपत्ति सार्वजनिक

हर उम्मीदवार अपने पूरे परिवार की संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा, पद पर रहते हुए हर वर्ष।

4. भ्रष्ट? निष्कासित

एक स्वतंत्र सत्यनिष्ठा आयोग सदस्यों को, चुने जाने के बाद भी, निष्कासित कर सकता है, और पार्टी उन्हें पद से हटवाने का हर विधिसम्मत प्रयास करती है।

5. नेता और मंत्री पहले घोषित

मुख्यमंत्री उम्मीदवार और मुख्य मंत्री मतदान से पहले घोषित, न्यूनतम योग्यताओं के साथ (जैसे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर)।

6. किसी भी दल के अच्छे विचारों का समर्थन

विरोधी दल के प्रस्ताव का केवल इसलिए विरोध नहीं, और सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं।

7. बड़े निर्णय सदस्य लेंगे

हर गठबंधन को सदस्य मंजूरी देंगे, घोषणापत्र लिखेंगे और पदाधिकारियों को वापस बुला सकेंगे। हर वादे की स्वतंत्र लागत आँकी जाएगी।

8. हर रुपया सार्वजनिक

दान 7 दिनों में दिखाए जाएँगे; मासिक लेखे और ₹10,000 से अधिक का हर भुगतान वेबसाइट पर।

9. सत्ता बँटी हुई

कार्यकाल सीमा, मौजूदा विधायकों को फिर प्राइमरी लड़नी होगी, मंत्री पार्टी नहीं चला सकता, पार्टी निकायों में एक-तिहाई महिलाएँ, और युवा शाखा को मताधिकार।

10. छोटी शुरुआत, सही तरीके से

दिल्ली से शुरुआत; फिर एक-एक करके अन्य राज्य।



पार्टी का संगठन

स्तर 1

सदस्य

निर्वाचक नामावली में दर्ज कोई भी व्यक्ति। निःशुल्क साधारण सदस्यता, या ₹100 प्रति वर्ष। सदस्य प्राइमरी में मत देते हैं।

स्तर 2

कार्यकारी सदस्य

पार्टी चलाते हैं और प्राइमरी लड़ सकते हैं। संचालन व्यय के लिए ₹1,000 प्रति माह, कम आय वालों के लिए छूट।

स्तर 3

सलाहकार परिषदें

राष्ट्रीय और हर राज्य में 21 प्रतिष्ठित नागरिक। वे सलाह देते हैं और प्रकाशित मानदंडों पर तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ सकता है; स्वयं कभी चुनाव नहीं लड़ते।

आपसे हमारा अनुरोध

कृपया इसे पढ़ें, और समय हो तो संविधान का पूरा प्रारूप भी, फिर अपने ईमानदार उत्तर भेजें। प्रशंसा से अधिक आलोचना उपयोगी है।

1. एक पंक्ति में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
2. आपको कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा?
3. कौन सा विचार आपको सबसे अधिक चिंतित करता है, और क्यों?
4. क्या कुछ अस्पष्ट या अविश्वसनीय लगता है?
5. कम आय वालों की छूट के साथ, कार्यकारी सदस्यों के लिए ₹1,000 प्रति माह उचित है?
6. जाति के बजाय आर्थिक आवश्यकता पर आधारित आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है?
7. क्या मंत्रियों के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए?
8. क्या आप सदस्य बनेंगे? क्या आप कभी प्राइमरी लड़ना चाहेंगे?
9. और किसे यह देखना चाहिए? (आगे भेजने से पहले कृपया पूछ लें।)

यह एक प्रारंभिक, निजी प्रारूप है, जो सार्वजनिक परामर्श से पहले परिवार और मित्रों के साथ साझा किया जा रहा है। कृपया इसे अभी सोशल मीडिया पर न डालें। संविधान का पूरा प्रारूप हिंदी और अंग्रेज़ी में अनुरोध पर उपलब्ध है।